>

Title: Regarding the pitiable condition of rural Beedi workers in the country.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोकमहत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आपका ध्यान बीड़ी मजदूरों के शोषण की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में लाखों की संख्या में बीड़ी मजदूर हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी काम करते हैं। बीड़ी मजदूरों के लिए कम्पलसरी कर दिया जाए कि उनका कार्ड बनाया जाए।

दूसरी बात, उनकी जो भी निर्धारित मजदूरी होती है, उस मजदूरी में मालिक बीड़ी के डैमेज को दिखा कर उसकी मजदूरी में से काट लेता है। उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। कई बीड़ियां अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आती हैं, उन पर प्रदेश में आने के लिए प्रवेश शुल्क लगे, ताकि उत्तर प्रदेश में जो बीड़ी निर्मित होती है, उसका प्रदेश के लोग ज्यादा उपयोग करें। अन्य प्रदेशों से जो बीड़ी आती है, उस पर प्रवेश शुल्क लगाया जाए। बीड़ी मजदूरों के आवास के लिए निशुल्क आवासीय पट्टे की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बीड़ी मजदूरों को आवास बनाने के लिए जो आर्थिक अनुदान दिया जाता है, वह बहुत नामिनल है। हमारी मांग है कि उसे एक लाख रुपए कम से कम किया जाए। उनकी पुत्रियों की शादी के लिए केवल पांच हजार रुपए दिए जाते हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार इस राशि को बढ़ा कर 25 हजार रुपए करे।

इन श्रमिकों को सामूहिक बीमा योजना में स्वाभाविक दुर्घटना में मृत्यु लाभ की राशि को एक लाख किया जाए। जिन श्रमिकों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें पेंशन का हकदार बनाया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में मैंने जैसा कहा कि लाखों की संख्या में बीड़ी मजदूर हैं, उनके लिए अलग से कम से कम 10 या 20 कमरों का अस्पताल बने, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पेथोलोजी की व्यवस्था हो। बीड़ी मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा में अनुदान स्कोलरशिप कम्पलसरी कर दिया जाए। कौशाम्बी में भरवारी जगह है, जहां इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल गाड़ी जाती है और इनके स्वास्थ्य का परीक्षण करती है, वह गाड़ियां नहीं जाती हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तमाम बिंदुओं पर बीड़ी मजदूरों का जो शोषण हो रहा है और उनके लिए कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन पर सरकार ध्यान दे और अमल करे।